

देश की उपासना

सान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 अंक - 314 जौनपुर, शनिवार, 10 अगस्त 2024 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज - 4 मूल्य - 2 रूपये

पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले किया हर घर तिरंगा अभियान का आगाज

सीएम ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का किया शुभारंभ

नई दिल्ली, एजेंसी। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2024 से पहले खास अभियान की शुरुआत की है। भारत अपने 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारी में है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को देश के नागरिकों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। इस अपील के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक प्रोफाइल की डिस्प्ले पिक्चर को भी बदल दिया है। सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर तिरंगा लगाया है। उन्होंने जनता से भी प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगा लगाने की अपील की है। इसके अलावा



उन्होंने एक लिंक भी साझा किया है। इसके जरिए लोगों से हर घर तिरंगा अभियान के जरिए जुड़ने की अपील की है। जनता से राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी सेल्फी को साझा करने का अनुरोध किया है। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में

पीएम मोदी ने लिखा, इस साल स्वतंत्रता दिवस के करीब आते ही, आइए हम फिर से रुहरघरतिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन वज के साथ अपनी सेल्फी को साझा करने का अनुरोध किया है। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में

मनाने में मेरा साथ देने का आग्रह करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 11 अगस्त से पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी 11 अगस्त से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा भी निकालेगी। इस दौरान हर घर, दुकान और दफ्तर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। पीएम मोदी ने सभी भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए शहर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी लेने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने के बढ़ते चलन पर प्रकाश डाला। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह

किया कि घरों, कार्यालयों और दुकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। इसे 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। इस पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत आजादी के 75 साल पूरे होने और अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाया जाता

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की वीर भूमि काकोरी में शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत वीरों के नमन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन करने हुए डाक अनावरण व संस्कृत विभाग द्वारा निर्मित पुस्तिका का विमोचन किया और बच्चों के साथ काकोरी शहीद मंदिर के बाहर सेल्फी भी ली। सीएम योगी ने इस अवसर पर कहा कि अब भारत का समय आ गया है, दुनिया की कोई शक्ति हमें महाशक्ति बनने से रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो पंच प्रण दिलाए गए हैं, उनको देश के हर नागरिक को आत्मसात



करना होगा। यही हमारे अमर बलिदानियों और शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर हम इन प्रण को आत्मसात करके अपने कार्यों को पूरा करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमारा देश विश्वगुरु और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति

न बने। सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन को याद करते हुए कहा कि देश से बाहर जा रहे राजस्व को देश सेवा में प्रयुक्त करने को पूरा करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमारा देश विश्वगुरु और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति

भारतीय हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर खेल मंत्री मांडविया ने दी बधाई

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने यह लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल जीता है। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को मात देकर कांस्य पदक जीता था। यह ओलंपिक में भारतीय हॉकी के लिए 13वां मेडल है। इस मैच में भारत की जीत को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कांस्य पदक जीतने पर केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 'हॉकी टीम की कांस्य पदक जीत के लिए सभी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भारतीय पुरुष हॉकी

टीम के कांस्य पदक जीतने पर केंद्रीय रेलवे एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिंदू का कहना है, 'हॉकी टीम की कांस्य पदक जीत के लिए सभी को बधाई देता हूँ। इस बार पंजाब के ज्यादा खिलाड़ी थे। हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। पंजाब और देश की तरफ से खिलाड़ियों को ढेर सारी बधाईयां।

भारतीय हॉकी टीम का पेरिस ओलंपिक का अभियान अच्छा रहा। हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके अगले मैच में अर्जेंटीना के साथ भारत का मैच 1-1 से ड्रा हुआ था। इसके अगले ही दिन 30 जुलाई को भारत ने आयरलैंड को 2-0 से हराया।

17 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए सिसोदिया

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आए। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दिल से इनकार किया। उन्होंने कहा कि संविधान की ताकत की वजह से जमानत मिली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निर्दोष लोगों को संविधान बचाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसी संविधान की ताकत की बदौलत अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने समर्थकों के बीच जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जेल के तले टूटते अरविंद केजरीवाल भी छूटेंगे। आप नेता ने



कहा कि सुबह जब से ये आदेश आया है, मेरा रोम-रोम बाबा साहब का ऋणी महसूस कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि बाबा साहब का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा। आप नेता ने कहा कि सुबह जब से ये आदेश आया है, मेरा रोम-रोम बाबा साहब का ऋणी महसूस कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि बाबा साहब का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपके प्यार,

ईश्वर के आशीर्वाद और सत्य की शक्ति के कारण जेल से बाहर आया हूँ, और सबसे बड़ी बात, बाबासाहेब का सपना है कि अगर कोई तानाशाह सरकार सत्ता में आती है और तानाशाही कानून बनाकर विश्वी नेताओं को सलाखों के पीछे डालती है, तो इस देश का संविधान उनकी रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संविधान की इसी शक्ति से अरविंद

केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। इससे पहले आज ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की आबकारी नीतिमें कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी और न्यायमूर्ति वी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले का सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। पीठ ने कहा कि इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस बात को समर्थक कि जमानत नियम है और जेल अपवाद।

नीतीश ने गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर पर अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश

पटना, एजेंसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना और अन्य स्थानों पर गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को अलर्ट रहने एवं सारी तैयारी पूर्ण रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पटना में जेपी गंगा पथ कंगन घाट, काली घाट, गांधी घाट एवं कृष्णा घाट पर रुककर गंगा नदी के आसपास की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह अलर्ट रहें और सारी तैयारी पूर्ण रखें। अशोक राजपथ

को जेपी गंगा पथ से मिलानेवाले कृष्णा घाट पर निर्माणाधीन पहुँच पथ की भी मुख्यमंत्री ने जानकारी ली और तेजी से निर्माण पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त-सह-जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चौथन प्रसाद, पटना के जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों के मुताबिक, गंगा नदी पटना जिले के गांधी घाट और हाथीदह तथा आसपास के इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर रह रही है। उन्होंने बताया कि भागलपुर जिले के कुछ इलाकों में भी गंगा नदी खतरे के निशान को छू गई है।

न्यूज डायरी ड्यूटी से गायब 15 चिकित्साधिकारी होंगे बरखास्त

लखनऊ, संवाददाता। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में लंबे समय से ड्यूटी न करने वाले 15 चिकित्साधिकारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्यवाही होगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ साखी सेन शर्मा को निर्देश दिया है। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अड्डा बाजार (महाराजगंज) में कार्यरत डॉ. अरशद जमाल की लगातार अनुपस्थिति चल रहे हैं। इन्हें पूर्व में निलंबित किया गया। अब मंडलीय अपर निदेशक की जांच रिपोर्ट के बाद उन्हें भी बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध - मुख्य निर्वाचन आयुक्त

जम्मू, एजेंसी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति को चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुमार ने यह संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में सभी दल विधानसभा चुनाव कराने का "पुरजोर समर्थन" कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी आंतरिक या बाहरी शक्ति को चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर में सभी राजनीतिक दल जल्द से जल्द विध

ानसभा चुनाव कराने का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव के लिए प्रशासनिक व शामिल हैं।



शुक्रवार को बताया कि शुक्रवार को यात्रा के दूसरे दिन प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लो और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रमुख आर. आर. रवैन से मुलाकात की। जम्मू-कश्मीर में 2014 से विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं।

भारत और बांग्लादेश सीमा की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन

नई दिल्ली, एजेंसी। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए मोदी सरकार ने पड़ोसी देश से लगती अपनी सभी सीमाओं पर सुरक्षा पहले से ही कड़ी कर दी थी और अब सरहद के हालात पर निगरानी रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। भारत-बांग्लादेश के सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए जिस समिति का गठन किया गया है वह बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक करने के लिए बांग्लादेश के समकक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेगी। हम आपको बता दें कि अपर महानिदेशक (एडीजी) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पूर्वी कमांड इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति ने अन्य सदस्यों में महानिरीक्षक (आईजी) बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल, महानिरीक्षक (आईजी)

बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा, सदस्य (योजना और विकास) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और सचिव शामिल हैं। हम आपको बता दें कि इस समिति का गठन ऐसे समय किया गया है जब भारत-बांग्लादेश सीमा पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। इन लोगों में बांग्लादेश के हालात से त्रस्त वहां की जनता के अलावा वहां रह रहे भारतीय नागरिक भी हैं। ऐसे में बीएसएफ के लिए कार्य काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। हाल ही में असम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था कि सभी भारतीय पासपोर्ट धारकों को राज्य में निर्दिष्ट प्रवेश बिंदु के माध्यम से संकटग्रस्त बांग्लादेश से लौटने की अनुमति दी जाएगी, जबकि अन्य को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि असम पुलिस और सीमा सुरक्षा बल गैर-भारतीयों के देश में अवैध रूप से



प्रवेश के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा था, 'हमारी ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि हम किसी को भी असम में अवैध रूप से प्रवेश नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा था कि निर्देश

अन्य को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि कोई भी (अवैध रूप से) प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो हम कानून के अनुसार कार्यवाही करेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने

उपचुनाव के लिए अखिलेश ने तैयार किया मास्टर प्लान

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी (सपा) अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर अपना प्लान तैयार कर लिया है। ध्यान केंद्रित करती दिख रही है। पार्टी अपनी रणनीति में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पहली और दूसरी पंक्ति के नेताओं का मिश्रण तैयार कर रही है। सूत्रों से पता चला है कि सपा कई सीटों पर मौजूदा सांसदों के रिश्तेदारों को मैदान में उतारने की मंशा जता रही है।

उपवर्गीकरण के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाए सरकार - मायावती

लखनऊ, संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उच्चतम न्यायालय द्वारा



राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में 'बसपा' पर एक पोस्ट में कहा, 'उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार दिये जाने के फैसले को

संविधान संशोधन के जरिये निष्प्रभावी करने पर जोर देते हुए शुक्रवार को यह आश्वासन देना कि कोटे में इसी सत्र में संविधान संशोधन विधेयक लाने की मांग की। मायावती ने 'एक्स्प्रेस' पर एक पोस्ट में कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मिलने गये भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)

के एससी-एसटी (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) सांसदों को यह आश्वासन देना कि कोटे में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने तथा एससी-एसटी के आरक्षण में कोई उप-वर्गीकरण भी नहीं करने की उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा, यह उचित है और ऐसा किए जाने पर इसका स्वागत।' भाजपा सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और एससी व एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में यह भी कहा, 'लेकिन अच्छा होता कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष बहस में केंद्र सरकार की तरफ से एटार्नी जनरल द्वारा आरक्षण

को लेकर एससी व एसटी में क्रीमी लेयर लागू करना तथा इनका उप-वर्गीकरण किये जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गयी होती, तो शायद यह निर्णय नहीं आता।' बसपा प्रमुख ने अपने सिलसिलेवार पोस्ट में आशंका जाहिर करते हुए कहा, 'उच्चतम न्यायालय के एक अंगस्त 2024 के निर्णय को संविधान संशोधन के जरिए जब तक निष्प्रभावी नहीं किया जाता तब तक राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत वहां इस निर्णय का इस्तेमाल करके एससीएसटी वर्ग का उप-वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को लागू कर सकती हैं। अतः संविधान संशोधन बिल इसी सत्र में लाया जाए। उच्चतम न्यायालय ने एक अंगस्त को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा।

मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ किरेन रिजिजू ने की बैठक

नई दिल्ली, एजेंसी। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद



पूनावाला भी मौजूद थे। यह बैठक लोकसभा में 'वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024' पेश होने और विश्व के विरोध के बीच हुई। फिलहाल लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक

पर विचार करने के लिए संसद की संयुक्त समिति के गठन की खातिर सदन के 21 सदस्यों को नामित करने तथा राज्यसभा से 10 सदस्यों को नामित करने की अनुशंसा संबंध

यक्ष संयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बताया कि विभिन्न राज्यों से विभिन्न दरगाहों के सज्जादानशीन 11-12 लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री (किरेन रिजिजू) से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा कि यह अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद और विभिन्न अन्य संगठनों की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग थी। हम संसद के समक्ष वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश करने के भारत सरकार के फैसले की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ धाराएं बताई गई हैं, उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इससे पारदर्शिता आएगी। धन का दुरुपयोग रुकेगा। मुझे लगता है कि सभी की शंकाओं का समाधान होने के बाद एक बहुत अच्छा विधेयक सामने आएगा।

